‘राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्यपाल किसी विधेयक से यदि असहमत हैं तो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके विधेयकों में बदलाव कराने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकते

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक बार जब राज्यपाल विधेयकों पर सहमति रोक देते हैं तो वे विधेयक को हमेशा के लिए अपने पास रोककर ''विधेयक को ख़त्म'' नहीं कर सकते।**

नयी दिल्ली, 1 दिसंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा की ओर से भेजे गए विधेयक पर एक बार जब राज्यपाल सहमति नहीं देते तो बाद में यह नहीं कह सकते कि वह इसे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर यह टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि एक बार जब राज्यपाल सहमति रोक देते हैं तो वह इसे हमेशा के लिए रोककर ''विधेयक को ख़त्म'' नहीं कर सकते।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल के बीच हल करना होगा। पीठ ने कहा, ''यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं और उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों के निपटारे के संबंध में गतिरोध को हल करते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे।''

पीठ ने कहा, ''हम चाहते हैं कि राज्यपाल इस गतिरोध को दूर करें। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम उच्च संवैधानिक पद के साथ काम कर रहे हैं...संविधान के अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं। वह विधेयक पर सहमति दे सकते हैं। सहमति रोक सकते है या वह को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते है।

पीठ ने कहा, ''एक बार जब राज्यपाल सहमति रोक देते हैं तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता।'' अटॉर्नी जनरल के अपनी ओर से यह कहने पर कि यह एक खुला प्रश्न है और इसकी जांच की जानी चाहिए, पीठ ने कहा, हमने वह कानून बनाया है।यह हमारे फैसले (पंजाब के राज्यपाल मामले में) द्वारा शासित है।

पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद रखता है। इसलिए संविधान ने उसे अधिक व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं। पीठ ने कहा, केंद्र सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के मूल भाग में निर्दिष्ट तीन विकल्पों में से एक का उपयोग करना चाहिए।

अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि यदि राज्यपाल अनुमति रोकते हैं तो विधानसभा कहेगी कि हमें सहमति रोकने की परवाह नहीं है, ''हम विधेयक को एक बार फिर पारित करेंगे''। पीठ ने अटर्नी जनरल से पूछा, राज्यपाल के पास सहमति को रोकने की स्वतंत्र शक्ति है?'' पीठ कहा कि वह इस मसले पर अगले सप्ताह विचार करेगी। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को सवाल किया था कि जनवरी 2020 में सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर निर्णय लेने में तमिलनाडु के राज्यपाल तीन साल तक क्या कर रहे थे।

पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी मारा गया

- **मृत आतंकवादी की पहचान पिंजूरा शोपियां निवासी मोहम्मद अयूब अली के बेटे किफायत अयूब अली के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था।**

श्रीनगर 1 दिसंबर (वार्ता)। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने पुलवामा के अरिहाल गांव में गुरुवार को घेराबंदी और तलाश अभियान छेड़ा था। इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलायी। दोनों पक्षों के बीच चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया।

उन्होंने बताया कि मृत आतंकवादी की पहचान पिंजूरा शोपियां निवासी मोहम्मद अयूब अली के बेटे किफायत अयूब अली के रूप में हुई है।

‘हिन्द प्रशांत क्षेत्र में किसी भी समय टकरावपूर्ण स्थिति बन सकती है’

- **नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि, हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सामरिक महत्वकांक्षा इस क्षेत्र में शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा है।**
- **नौसेना में हाल ही में एक महिला अग्निवीर की आत्महत्या से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है।**

नयी दिल्ली, 1 दिसंबर (वार्ता)। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हिन्द प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह के विवाद हैं उनके कारण वहां किसी भी समय टकरावपूर्ण स्थिति बन सकती है लेकिन भारतीय नौसेना वहां कड़ी नजर रख रही है और हर स्थिती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है।

नौसेना प्रमुख ने नौसेना दिवस से पहले आज यहां वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिन्द प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूछे सवाल के जवाब में कहा कि वहां कुछ विवाद हैं और ये टकराव का रूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा वहां डकैती से लेकर तस्करी तथा आपदाओं के समय विभिन्न तरह के अभियान चलाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए परस्पर संवाद जरूरी है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत खुले , मुक्त, स्वतंत्र तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि हिन्द प्रशांत क्षेत्र में भारत हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहा है और किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है।

हिंद महासागर के बारे में एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि सागर साझा धरोहर माने जाते हैं । महासागरों में हर देश कानूनी रूप से अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। चीन को भी वहां आर्थिक गतिविधियों का अधिकार है। क्षेत्र में भारत एक नौसैनिक ताकत है और वह हर देश की गतिविधि पर करीबी नजर रखता है ।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय हितों की रक्षा करना नौसेना की प्राथमिकता है।

एडमिरल कुमार ने कहा कि जहां नौसेना के युद्धपोत और अन्य प्लेटफार्म हिन्द महासागर तथा हिन्द प्रशांत में तैनात रहते हैं वहीं हमारे प्लेटफार्म विभिन्न मित्र देशों की यात्राओं पर भी जाते हैं। इसके अलावा वे विभिन्न अभियानों में हिस्सा लेने के साथ-साथ अनेक देशों की नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त अभ्यास में भी हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इससे नौसेनाओं के बीच परस्पर विश्वास तो बढ़ता ही है इनमें तालमेल तथा सहयोग भी बढ़ता है। युद्धपोतों की विभिन्न जगहों पर तैनाती से जहां क्षेत्र में निगरानी की जाती है वहीं अलग-अलग अभियानों में हिस्सा लेने से उसकी विश्वसनीयता बढती है।

नौसेना के लिए दूसरे विमानवाहक पोत के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत बनाने के बाद अब नौसेना आश्वस्त है कि उसे इस क्षेत्र में महारत हासिल हो गयी है और अब अधिक आधुनिक विमानवाहक पोत को भी कम समय में बनाया जा सकता है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आयात पर निर्भरता कम होती है।

भारत ने विदेशों में छुपे 184 आर्थिक भगोड़ों की लॉकेशन का पता लगाया

सी.बी.आई. ने दावा किया कि, भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल के साथ मिलकर इन आर्थिक अपराधियों की गिरफ्तारी व स्वदेश वापसी की कवायद शुरु कर दी है

- **सी.बी.आई. के अनुसार, पहले ही इस वर्ष कम से कम 24 भगोड़ों की स्वदेश वापसी कराई जा चुकी है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग के परिणामस्वरूप 2021 से अब तक 65 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को वापस लाया गया है। पिछले साल जहां 27 अपराधियों को भारत वापस लाया गया, वहीं 2021 में 18 को वापस लाया गया था।**

नई दिल्ली,1 दिसम्बर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने विभिन्न देशों में 184 अपराधियों का पता लगा लिया है और इंटरपोल तथा संबंधित देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से उनकी वापसी के लिए औपचारिक कार्यवाही शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख दिनकर गुप्ता ने वियना में इंटरपोल की 91वीं आम सभा में ''अपराध, अपराधियों और अपराधों की आय के लिए किसी भी सुरक्षित आश्रय से इनकार करने'' पर जोर दिया।

संघीय भ्रष्टाचार निरोधक जांच एजेंसी पहले ही इस वर्ष कम से कम 24 भगोड़ों की वापसी करा चुकी है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग के परिणामस्वरूप 2021 से 65 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को वापस लाया गया है। पिछले साल जहां 27 अपराधियों को भारत वापस लाया गया, वहीं 2021 में 18 को वापस लाया गया।

सीबीआई ने एक बयान में कहा, ''2023 में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांटेड 24 अपराधियों और भगोड़ों को इंटरपोल चैनलों के माध्यम से करीबी सहयोग करके विदेश से भारत लौटाया गया था। यह एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक घटनाओं में से एक है। इसके अलावा, भारत ने विभिन्न देशों में 184 से अधिक अपराधियों का पता लगाया है और उनकी वापसी के लिए औपचारिक कार्यवाही शुरू की है। यह अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए इंटरपोल चैनलों के बढ़ते लाभ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संबंधों को दर्शाता है।''

भारतीय एजेंसियों द्वारा अपराधियों का जियोलोकेशन पता करने से तात्पर्य तकनीकी डेटा, फोन लोकेशन, आपराधिक गतिविधि और ह्यूमन इंटेलिजेंस सहित विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करके उनके ठिकाने का पता लगाना है। पिछले तीन वर्षों में विदेशों से वापस लाए गए कुछ भगोड़ों में सुभाष शंकर परब भी शामिल है।

मोदी ने गुटेरेस से की मुलाकात

दुबई, 1 दिसम्बर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां विश्व जलवायु कार्रवाई सम्मेलन से इतर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की।

मोदी ने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को धन्यवाद दिया। उन्होंने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की पहल और प्रगति पर प्रकाश डाला।

दोनों नेताओं ने जलवायु कार्रवाई, जलवायु प्रौद्योगिकी और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों तथा वित्तीय संस्थानों में सुधारों से संबंधित ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी20 अध्यक्षता के तहत सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री की ‘ग्रीन क्रेडिट’ पहल का स्वागत किया। गुटेरस ने भारत की जी20 अध्यक्षता की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 में आगे ले जाने के लिए भारत के साथ काम करने की पुष्टि की।

गाज़ा पट्टी में इज़राइली हमलों में 109 लोगों की मौत

इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि, हम हमास के पूरी तरह से खात्मे की कसम खा चुके हैं अब पीछे नहीं हट सकते

- **सीज़फायर खत्म होते ही इज़राइल ने फिर से हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ कई हमले किये।**
- **रिपोर्ट्स के अनुसार सीज़फायर के दौरान सबसे पहले हमास की ओर से इज़राइली क्षेत्र में हमले किये गये थे, उसके तुरंत बाद इज़राइल ने भी गाज़ा पट्‌टी पर जवाबी हमले शुरु कर दिये।**
- **हमलों से पहले इजराइल के रक्षा बलों ने कहा कि, हमास ने मानवीय विराम तोड़ दिया, जिससे इज़राइल को युद्ध फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।**

यरुशलेम/ट्ययूनिस, 1 दिसंबर (वार्ता/स्पूतनिक)। गाजा पट्टी पर शुक्रवार को इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 109 से अधिक हो गई है तथा बड़ी संख्या में लोग घायल हो गये। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

इससे पहले दिन में इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में हमास आंदोलन के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर दी है। उसने कहा कि उसने इजरायली क्षेत्र पर गोलीबारी करके मानवीय विराम का उल्लंघन किया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आज सुबह संघर्ष विराम खत्म होने के बाद से इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, संघर्ष विराम की समाप्ति के तीन घंटे के भीतर इजरायली कब्जे के नरसंहार के पीड़ितों की संख्या बढ़कर 32 हो गई। इनमें कई लोगों को अलग-अलग स्तर की चोटें लगीं। मृत और घायल लोगों में अधिकांश महिलायें और बच्चे शामिल हैं।

इससे पहले दिन में, इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि हमास ने मानवीय विराम तोड़ दिया, जिससे इज़राइल को युद्ध फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार देर रात रिपोर्ट दी कि दोनों पक्ष अस्थायी मानवीय विराम को आठवें दिन तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

इसकी हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नवीनतम संघर्षविराम आज स्थानीय समयानुसार सुबह 07:00 बजे समाप्त हो गया।

इजरायल और हमास के बीच एक सप्ताह के संघर्ष विराम की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद शुक्रवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा को फिर से निशाना बनाते हुए पूरी ताकत के साथ हमला शुरू शुरू किया। इजरायल के हवाई हमलों दक्षिण गाजा पर हमला किया, जिसमें खान यूनिस शहर के पूर्व में अबासन समुदाय रहते हैं। इजरायल के एक अन्य हवाई हमले ने गाजा शहर के उत्तर-पश्चिम में एक घर को निशाना बनाया। दक्षिण गाजा पट्टी में लगातार विस्फोटों की आवाज़ सुनायी दी गई और क्षेत्र से काला धुएं का गुब्बार निकलता दिखाई दिया।

इज़रायल में भी गाजा से सटे तीन इलाकों में सायरन की आवाज सुनी गयी और रॉकेट हमले की चेतावनी दी गयी। इलाके के लोगों को चेतावनी दी गयी कि कि हमास ने भी अपने हमले फिर से शुरू कर दिए हैं।

इजरायली सेना की नए सिरे से हमलों की घोषणा और एक सप्ताह से अस्थायी संघर्ष विराम आज सुबह सात बजे समापत होने के केवल आधे घंटे के बाद इजरायल ने गाजा पर हमले शुरू कर दिये। दोनों पक्षों की ओर से 24 नवंबर को संघर्ष विराम की अवधि शुरू हुयी थी और आज सुबह सात बजे यह अवधि समाप्त हो गयी थी।

गाजा की 23 लाख की अधिकांश आबादी अब दक्षिण गाजा में फंस गई है और वहां से निकलने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। इससे पहले इजरायल की सेना ने अपने शुरुआती बमबारी के दौरान हजारों लोगों को उत्तरी गाजा को खाली करने का निर्देश दिये थे।

इजरायल और गाजा के बीच सात अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अबतक 16,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

अब तीन को नहीं चार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिरलाई पावल (एमजेडपी) शामिल हैं।

आइजोल में राजभवन के पास रैली को संबोधित करते हुए एनजीओसीसी के अध्यक्ष लालहमछुआना ने निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक दलों, गिरजाघरों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बार-बार मतगणना की तारीख को बदलने की अपील के बावजूद इस मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया। लालहमछुआना ने कहा कि मतगणना की तारीख रविवार को पड़ती है, जो ईसाइयों के लिए एक पवित्र दिन है। उन्होंने कहा कि मिजोरम एक ईसाई बहुल राज्य है। उन्होंने कहा कि एनजीओसीसी ने हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पर चुप रहा और हमारी अपीलों का जवाब देने में विफल रहा।

सीवाईएमए के अध्यक्ष लालहमछुआना ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन मिजो समुदाय और उनके धर्म की रक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। मिजो हमीछे इंसुइहखावम पावल (एमएचआईपी) या मिजोरम महिला संघ, मिजो छात्र संघ (एमएसयू) और एमजेडपी जैसे अन्य संगठनों के नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया।

मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सात नवंबर को हुआ था। राज्य के 8.57 लाख पात्र मतदाताओं में से 80 फीसदी से अधिक ने मतदान किया है। कुल 174 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी 13 मतगणना केंद्रों और 40 मतगणना हॉल में सुबह आठ बजे गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी।

2.40 लाख रू. की रिश्वत लेते सरपंच गिरफ्तार

- **चित्तौड़गढ़ के जाड़ाना गांव के सरपंच संजय सुखवाल ने पट्टा जारी करने के एवज में यह रिश्वत ली है।**
- **उल्लेखनीय है कि आरोपी सरपंच शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 1 लाख रुपये ले चुका था।**

कपासन, 1 दिसम्बर (निसं)। एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संजय सुखवाल उर्फ संजू सरपंच, ग्राम पंचायत जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चितौड़गढ़ को परिवादी से 2 लाख 40 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई में परिवादी ने शिकायत की थी कि उसके कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में संजय सुखवाल उर्फ संजू सरपंच, ग्राम पंचायत जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चित्तौड़गढ़ 3 लाख 40 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है।

ए.सी.बी. के उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल की निगरानी में ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सान्दू के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया फिर संजय सुखवाल उर्फ संजू निवासी ग्राम जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चित्तौडगढ हाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाड़ाना, तहसील राश्मी, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 2 लाख 40 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सरपंच शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 1 लाख रुपये ले चुका था। ए.सी.बी. टीम उस राशि को बरामद करने का प्रयास कर रही है।

आरोपी सरपंच द्वारा हाल ही में जारी किये गये अन्य पट्टों के संबंध में भी ए.सी.बी. द्वारा जांच की जा रही है। ए.सी.बी. उप महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

फ्लाइट में महिला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की थी क्योंकि महिला की पल्स फिर बंद हो गई। हम करीब 30 मिनट तक लगातार कोशिश करते रहे लेकिन धड़कन बार-बार आ रही थी और थोड़ी देर में वापस बंद हो रही थी। पर हमने हार नहीं मानी और लगातार सीपीआर देते रहे जिससे बाद में महिला की धड़कन पूरी तरह से आ गई।

फ्लाईट में मौजूद लोगों को ये चमत्कार लग रहा था। वायुयान प्रबंधन ने जयपुर में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दी थी जिससे महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी महिला की अस्पताल से छुट्टी हो गई और वो पूरी तरह से स्वस्थ है।

अब तीन को नहीं चार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्नाटक में उनके खुद के ही कुछ रिज़ाट्र्स हैं। शुक्रवार को कर्नाटक के कुछ पत्रकारों ने जब शिवकुमार से पार्टी नेतृत्व द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि इसका श्रेष्ठतम निर्वहन करना उनका कर्त्तव्य है।

उन्होंने कांग्रेस के प्लान बी को लेकर कोई तथ्य नहीं छिपाया, जिसमें पार्टी की मुख्य चिन्ता अन्य राज्यों में भाजपा और तेलंगाना में अधिक साधन सम्पन्न बी.आर.एस. द्वारा कांग्रेस विधायकों की संभावित खरीद फरोख्त है। हम पिछले कई अवसरों पर शिवकुमार का जलवा पहले ही देख चुके हैं। एक बार तो उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तब मात दी थी जब भाजपा नेतृत्व अहमद पटेल को राज्यसभा चुनावों पराजित करवाना चाहता था और तब कर्नाटक का यह दिग्गज नेता कांग्रेस विधायकों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया था। जब तक वोटिंग शुरु नहीं हुई, कांग्रेस विधायक उनकी महफूज़ सरपरस्ती में रहे।

अब जबकि एग्ज़िट पोल्स ने तेलंगाना सहित कुछ राज्यों में कांटे के मुकाबले और त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की है तो एक बार फिर से ''रिज़ार्ट पॉलीटिक्स'' का समय आ सकता है।

गोवा में सर्वाधिक विधायकों को जिताने के बावजूद कांग्रेस वहां सरकार का गठन करने में विफल रही थी और उससे सबक लेकर इस बार वह भाजपा की चालों को लेकर अलर्ट है। भाजपा भी चौकस है और यदि जिताऊ विधायकों का आंकड़ा उसके पक्ष में नहीं रहता है तो भी वह सरकार बनाने का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहेगी।

तेलंगाना में तो भाजपा की दिली तमन्ना यही है कि मतगणना में त्रिशंकु विधानसभा के परिणाम आए ताकि वह अपन चुनिंदा विधायकों के साथ किंगमेकर की भूमिका अदा कर सके। एग्ज़िट पोल की भविष्यवाणियों के अनुसार भाजपा 3 से 5 सीटें जीतकर ए.आई.एम.आई.एम. के बाद चौथे स्थान पर रहेगी। ए.आई.एम.आई.एम. के सात सीटें जीतने की संभावना है और उसकी वर्तमान में भी इतनी ही सीटें हैं।

उम्मीद है कि कांग्रेस 60 से अधिक सीटें जीतकर तेलंगाना में सरकार का गठन करेगी, लेकिन यदि पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े से थोड़ा सा भी दूर रह जाती है या पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों दल-बदल अथवा इस्तीफा देने के लिए प्रलोभित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का प्लान बी भी तैयार है। इसीलिए अपने बहुमूल्य लोगों को संरक्षित करने के लिए पार्टी ने एक आपातकालीन योजना बनाई है और इस काम के लिए डी.के. शिवकुमार से अधिक योग्य कौन हो सकता है?

नवम्बर में जी.एस.टी. कलैक्शन 1.68 लाख करोड़ से अधिक

- **यह राशि पिछले वर्ष के इसी महीने में संग्रहित 145867 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।**

नयी दिल्ली, 1 दिसंबर (वार्ता)। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह इस वर्ष नवंबर में 1.68 लाख करोड़ रुपये के करीब रहा है जो पिछले वर्ष के इसी महीने में संग्रहित 145867 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्त वर्ष में यह छठवां महीना है जब जीएसटी राजस्व संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष नवंबर में कुल जीएसटी संग्रह 167929 करोड़ रुपये रहा है। इसमें सीजीएसटी 30420 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 38226 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 87009 करोड़ रुपये जिसमें आयातित वस्तुओं पर संग्रहित कर 39198 करोड़ रुपये भी शामिल है। क्षितपूर्ति अधिभार के रूप में 12274 करोड़ रुपये संग्रहित हुये हैं ।

बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोपी को सस्पेंड कर शास्त्रीनगर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। यह गबन यूनियन बैंक की दो शाखाओं बासनी और जालोरी गेट पर हुआ है।

आरोपी अप्रैल 2023 से जोधपुर की सोजती गेट ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इसी ब्रांच के मैनेजर ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

शास्त्रीनगर पुलिस थाना प्रभारी मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि सोजती गेट स्थित यूनियन बैंक के प्रबंधक चेतन प्रकाश ने गुरुवार रात गबन का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने यूनियन बैंक (सोजती गेट) के सह प्रबंधक आकाश वर्मा पर साल 2021 से अप्रैल 2023 तक करीब दो साल में बासनी और जालोरी गेट ब्रांच में रहते हुए एक करोड़ रुपए का गबन करने के आरोप लगाए।

थाना प्रभारी ने बताया कि धोखाधड़ी काफी शातिर तरीके से की गई है। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। बैंक से रिकॉर्ड प्राप्त किए गए हैं। जिस-जिस पर संदेह है, सबको बुलाकर जांच करेंगे। पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी ने कुल कितने रुपए की धोखाधड़ी की है। बैंक ऑडिट में साफ होगा कि कुल कितना नुकसान हुआ है।

सूत्रों के अनुसार आकाश वर्मा 2016 से यूनियन बैंक में है। अब तक बासनी ब्रांच से करीब 35 लाख रुपए का गबन सामने आया है। आरोपी ने बासनी और जालोरी गेट ब्रांच में काम किया था। वहां के सभी रिकॉर्ड पुलिस ने मंगवाए हैं। बैंक प्रशासन भी अपने स्तर पर गबन का पता लगाने में जुट गया है। बैंक अधिकारियों की ओर से ऑडिट की जा रही है।

पिछले दो साल में असिस्टेंट मैनेजर आकाश वर्मा यूनियन बैंक जोधपुर की बासनी और जालोरी गेट स्थित शाखा में कार्यरत रहा था। इन्हीं शाखाओं में रहते हुए उसने गड़बड़ की। इसके बाद वह सोजती गेट शाखा में आ गया। वर्तमान में वह सोजती गेट शाखा में सह प्रबंधक था।

बासनी और जालोरी गेट शाखा में रहते हुए उसने फर्जी डॉक्युमेंट के जरिए कई क्रेडिट कार्ड जारी किए, खुद उनका वैरिफिकेशन किया। फिर दोस्तों, रिश्तेदारों के बिजली बिल, अन्य बिल, शॉपिंग व अन्य खर्चों के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देता। बदले में उनसे कैश ले लेता था। इस तरह दो साल में उसने 1 करोड़ से ज्यादा का गबन किया।

जानकारी के अनुसार दोनों बैंक शाखाओं में जब 20 क्रेडिट कार्ड के 1 करोड़ से ज्यादा के बिल लंबे समय से बकाया आए तो मामला उजागर हो गया। आकाश ने काफी शातिर तरीके से बैंक से धोखाधड़ी की। उसने असिस्टेंट मैनेजर पद का फायदा उठाया। पहले क्रेडिट कार्ड जारी करवाए, फिर वैरिफिकेशन में धांधली की। उसने सभी कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए रखी, ताकि अधिक से अधिक फ्रॉड किया जा सके। सभी कार्ड वह अपने पास ही रखता था और जरूरत के वक्त दोस्तों-रिश्तेदारों को देता था।

आरोपी आकाश ने पिछले दो साल में इन सभी कार्ड की पूरी लिमिट करीब 1 करोड़ रुपए यूज़ कर ली थी। इसके बाद बिलों का पैसा वापस बैंक में जमा नहीं कराया, जिसके कारण बैंक प्रशासन ने बकाया राशि को लेकर जांच की।

बहरहाल शास्त्रीनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक से संबंधित दस्तावेज मंगवाए गए हैं।

बैंक अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दो साल से 20 क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बकाया चल रहा था। बैंक के कर्मचारियों ने इन क्रेडिट कार्ड के लिए लगाए गए दस्तावेज खंगाले तो कोई जानकारी नहीं मिली। जिनके डॉक्युमेंट लगे थे, उन्होंने कहा कि वे क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते। जांच की तो पता चला कि सभी कार्ड एक ही अधिकारी (आकाश वर्मा) ने वैरिफाई किए हैं। जिन लोगों के नाम पर ये क्रेडिट कार्ड थे, वे या तो आकाश के दोस्त निकले, या फिर रिश्तेदार। इसके बाद मामला साफ हो गया।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908